भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5166 का उत्तर

टपरी-मुजफ्फरनगर रेल लाइन का दोहरीकरण/विद्युतीकरण

5166. श्री हाजी फजलुर रहमानः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) टपरी से मुजफ्फरनगर रेल लाइन के दोहरीकरण/विद्युतीकरण हेतु अनुमोदित परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजना में देरी का क्या कारण है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

mm

टपरी-मुजफ्फरनगर रेल लाइन के दोहरीकरण/विद्युतीकरण के संबंध में दिनांक 24.07.2019 को लोक सभा में श्री हाजी फजलुर रहमान के अतारांकित प्रश्न सं. 5166 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): मुजफ्फरनगर से टपरी (52 कि.मी.) के बीच विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण का कार्य 2015-16 में स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना की लागत 376.78 करोड़ रुपए है। कार्य शुरु कर दिया गया है। मार्च 2019 तक इस परियोजना के लिए 188.25 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और वर्ष 2019-20 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग): किसी रेल परियोजना का समय से शुरु करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालय के आदेश, आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना की निष्पांदन के समय और लागत को प्रभावित करते हैं जिसके कारण परियोजना को पूरा करने के लिए, फिलहाल कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

समग्र राष्ट्र के हित में और लागत में वृद्धि हुए बिना परियोजनाएं समय पर पूरी करना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर एवं बोर्ड स्तर) पर निगरानी की जाती है तथा राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों का समाधान किया जा सके।

इसके अलावा, परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने हेतु सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने ठेकों में बोनस खंड के रूप में ठेकेदारों के लिए प्रोत्साहन अवधारणा अपनाई है, जिससे परियोजनाओं के निष्पादन में और तेजी आएगी।

mm

इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण परियोजनाओं/क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं/लास्ट माइल संपर्कता परियोजनाओं आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था करके संस्थागत वित्तपोषण किया गया है, जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

****

mm